

डीप ओशन मशिन

प्रलिमिस के लायि:

डीप ओशन मशिन, बलू इकॉनमी, मानवयुक्त सबमरसिल व्हीकल, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी, इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी।

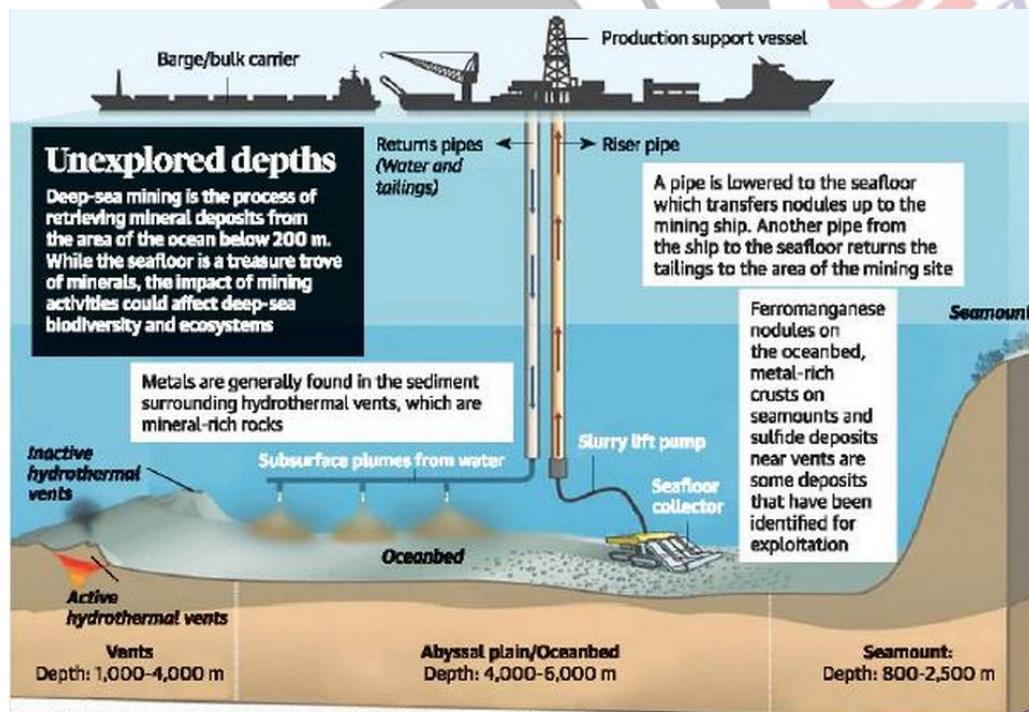
मेन्स के लायि:

डीप ओशन मशिन, सरकारी नीतियाँ और हस्तक्षेप, वैज्ञानिक नवाचार और खोजें, बलू इकॉनमी।

चर्चा में क्यों?

हाल ही में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा **डीप ओशन मशिन** (Deep Ocean Mission- DOM) लॉन्च किया गया है।

- DOM भारत सरकार की बलू इकॉनमी पहल का समर्थन करने हेतु एक मशिन मोड प्रोजेक्ट है।
- इससे पूर्व पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने **बलू इकॉनमी** पॉलिसी का मसौदा भी तैयार किया गया था।
- बलू इकॉनमी आरथिक विकास, बेहतर आजीविका और रोजगार एवं स्वस्थ महासागर पारस्परिकी तंत्र के लायि समुद्री संसाधनों का सतत उपयोग है।



Source: International Union for Conservation of Nature. Nature Journal

प्रमुख बढ़ि

DOM के प्रमुख घटक:

- मानवयुक्त सबमरसिल वाहन का विकास:
 - तीन लोगों को समुद्र में 6,000 मीटर की गहराई तक ले जाने के लायि वैज्ञानिक सेंसर और उपकरणों के साथ एक मानवयुक्त पनडुब्बी

- वकिसति की जाएगी ।
- NIOST और इसरो संयुक्त रूप से एक मानवयुक्त सबमरसबिल वाहन/पनडुब्बी वकिसति कर रहे हैं ।
- राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान (NIOST), पृथ्वी वजिज्ञान मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संस्थान है ।
- गहरे समुद्र में खनन हेतु प्रौद्योगिकी का वकिसति:
 - मध्य हृदि महासागर में पॉलीमेटेलिक नोड्यूलस के खनन के लिये एक एकीकृत खनन प्रणाली भी वकिसति की जाएगी ।
 - पॉलीमेटेलिक नोड्यूलस समुद्र तल में मौजूद लोहे, मैग्नीज़, निकिल और कोबाल्ट युक्त चट्टानें हैं ।
 - भविष्य में संयुक्त राष्ट्र के संगठन 'इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी' द्वारा जब भी वाणज्यिक खनन कोड तैयार किया जाएगा ऐसी स्थिति में खनजिंजी के अन्वेषण अध्ययन से निकिट भविष्य में वाणज्यिक दोहन का मार्ग प्रशस्त होगा ।
- महासागर जलवायु प्रविरत्न सलाहकार सेवाओं का वकिसति:
 - इसके तहत जलवायु प्रविरत्नों के भविष्यित अनुमानों को समझने और उसी के अनुरूप सहायता प्रदान करने वाले अवलोकनों एवं मॉडलों के एक समूह का वकिसति किया जाएगा ।
- गहरे समुद्र में जैव विविधता की खोज एवं संरक्षण के लिये तकनीकी नवाचार:
 - इसके तहत सूक्ष्मजीवों सहित गहरे समुद्र की वनस्पतियों और जीवों के सर्वेक्षण एवं गहरे समुद्र में जैव-संसाधनों के सतत उपयोग संबंधी अध्ययन पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा ।
- गहरे समुद्र में सर्वेक्षण और अन्वेषण:
 - इस घटक का प्राथमिक उद्देश्य हृदि महासागर के मध्य-महासागरीय भागों के साथ बहु-धातु हाइड्रोथर्मल सलफाइड खनजि के संभावित स्थलों का पता लगाना और उनकी पहचान करना है ।
- महासागर से ऊर्जा और मीठा पानी:
 - इसमें अपतीय '[महासागर थर्मल ऊर्जा रूपांतरण](#)' (OTEC) [वलिवणीकरण संयंत्र](#) हेतु अध्ययन और वसितृत इंजीनियरिंग डिज़ाइन तैयार करना शामिल है ।
 - OTEC एक ऐसी तकनीक है, जो ऊर्जा दोहन के लिये सतह से समुद्र के तापमान के अंतर का उपयोग करती है ।
- महासागर जीववजिज्ञान हेतु उन्नत समुद्री स्टेशन:
 - इस घटक का उद्देश्य महासागरीय जीव वजिज्ञान और इंजीनियरिंग में मानव क्षमता एवं उदयम का वकिसति करना है ।
 - यह घटक ऑन-साइट बज़िनेस इनक्यूबेटर सुविधाओं के माध्यम से अनुसंधान को औद्योगिक अनुपर्योग और उत्पाद वकिसति में प्रविरत्नति करेगा ।

‘डीप ओशन मशिन’ का महत्व:

- महासागरीय संसाधनों का लाभ उठाना: महासागर वशिव के 70% हसिसे को कवर करते हैं और हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हसिसा हैं । महासागरों की गहराई में स्थिति लगभग 95 प्रतशित हसिसा ऐसा है जिसिका अब तक अन्वेषण नहीं किया जा सका है ।
 - भारत तीन दशियों से महासागरों से घरि हुआ है और देश की लगभग 30 प्रतशित आबादी तटीय क्षेत्रों में रहती है, साथ ही महासागर मत्स्यपालन, जलीय कृषि, प्रयटन, आजीवकिए एवं 'बलू इकॉनमी' का समर्थन करने वाला एक प्रमुख आरथिक कारक है ।
 - संवन्धनीयता पर महासागरों के महत्व को ध्यान में रखते हुए संयुक्त राष्ट्र ने 2021-2030 के दशक को सतत वकिसति हेतु महासागर वजिज्ञान के दशक (*Decade of Ocean Science for Sustainable Development*) के रूप में घोषित किया है ।
- लंबी तटरेखा: भारत की समुद्री स्थितिअद्वतीय है । इसकी 7,517 कर्मी लंबी तटरेखा में नौ तटीय राज्य और 1,382 दीपी हैं ।
 - फरवरी 2019 में प्रतपादित किये गए भारत सरकार के **2030** तक के नए भारत के वकिसति की अवधारणा (*India's Vision of New India by 2030*) के दस प्रमुख आयामों में से बलू इकॉनमी भी एक प्रमुख आयाम है ।
- तकनीकी वशिष्जूत्राता: ऐसे मशिनों के लिये आवश्यक तकनीक और वशिष्जूत्राता वर्तमान में केवल पाँच देशों- अमेरिका, रूस, फ्रांस, जापान और चीन के पास उपलब्ध है ।
 - भारत ऐसी तकनीक वाला छठा देश होगा ।

नीली अर्थव्यवस्था/बलू इकॉनमी से संबंधित अन्य पहलें:

- सतत वकिसति के लिये नीली अर्थव्यवस्था पर भारत-नॉर्वे टास्क फोर्स:
 - भारत और नॉर्वे के बीच बलू इकॉनमी को लेकर संयुक्त पहल वकिसति करने के उद्देश्य से वर्ष 2020 में दोनों देशों द्वारा संयुक्त रूप से इस टास्क फोर्स का गठन किया गया था ।
- सागरमाला परयोजना:
 - [सागरमाला परयोजना](#) बंदरगाहों के आधुनिकीकरण के लिये आईटी-सक्षम सेवाओं के व्यापक उपयोग के माध्यम से बंदरगाह के वकिसति हेतु रणनीतिक पहल है ।
- ओ-स्मार्ट (O-SMART):
 - [ओ-स्मार्ट](#) एक अम्बरेला योजना है जिसिका उद्देश्य सतत वकिसति के लिये महासागरों और समुद्री संसाधनों का वनियमित उपयोग करना है ।
- एकीकृत तटीय क्षेत्र प्रबंधन:
 - यह तटीय और समुद्री संसाधनों के संरक्षण तथा तटीय समुदायों के लिये आजीवकिए के अवसरों में सुधार पर केंद्रित है ।
- राष्ट्रीय मत्स्य नीति:
 - भारत में समुद्री और अन्य जलीय संसाधनों से मत्स्य संपदा के सतत उपयोग पर ध्यान केंद्रित कर 'बलू ग्रोथ इनशिएटिव' को बढ़ावा देने हेतु एक राष्ट्रीय मत्स्य नीति मौजूद है ।

वगित वर्षों के प्रश्न

पर. यदिराष्ट्रीय जल मशिन को सही ढंग से और पूरणतः लागू किया जाए तो देश पर क्या प्रभाव पड़ेगा? (2012)

- 1- शहरी क्षेत्रों की जल आवश्यकताओं की आंशिक आपूर्ति अपशिष्ट जल के पुनर्चक्रण से हो सकेगी।
- 2- ऐसे समुद्रतटीय शहर-जनिके पास जल के अपर्याप्त वैकल्पिक स्रोत हैं, की जल आवश्यकताओं की आपूर्तिएसी समुचित पौद्योगिकी व्यवहार में लाकर की जा सकेगी, जो समुद्री जल को प्रयोग लायक बना सकेगी।
- 3- हमिलय से उदामति सभी नदियाँ प्रायद्वीपीय भारत की नदियों से जोड़ दी जाएंगी।
- 4- सरकार कृषकों द्वारा भौम जल निकालने के लिये बोरगि से खोदे गए कुएँ और उन पर लगाइ गई मोटर तथा पम्प-सेट पर वहन किये व्यय की पूरी तरह प्रतिपूर्ति कियेगी।

नीचे दिये गए कूट के आधार पर सही उत्तर चुनिये:

- (a) केवल 1
- (b) केवल 1 और 2
- (c) केवल 3 और 4
- (d) 1, 2, 3 और 4

उत्तर: (b)

स्रोत: पी.आई.बी.

PDF Reference URL: <https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/deep-ocean-mission-2>

